Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 5, October-2022, ISSN 2230-7540

समाज में दलित महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याएं

Neha Maurya*

Research scholar, Sociology department, Lucknow university, Lucknow

सार - ***महिलाओं ने हमेशा समाज में पुरुषों द्वारा प्राप्त एक अलग स्थान पर कब्जा कर लिया है, महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है। प्रत्येक समाज में अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं, उच्च पदों पर महिलाएं और निम्न पदों पर भी हैं, लेकिन हर सम्मान पिछड़ों की श्रेणी में आता है। परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक व्यवस्था के हर पहलू में महसूस किया जा रहा है, यह कुछ मामलों में तेज हो सकता है और दूसरों में यह धीमा भी हो सकता है। इन परिवर्तनों का महिलाओं पर अधिक प्रभाव पड़ा है, विशेषकर दलित महिलाओं पर, क्योंकि वे पिछड़ों में पिछड़ी हुई हैं। भारतीय समाज में उच्च स्तर की महिलाओं की तुलना में उनमें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है। इस प्रकार, भारत में दलित महिलाओं की बदलती स्थिति पर एक अध्ययन न केवल सामाजिक परिवर्तनों के व्यापक पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक और सार्थक है, बल्कि सबसे उत्पीड़ित निचले समूहों के बीच नेतृत्व के उभरते पैटर्न को समझना भी काफी आवश्यक है।***

कीवर्ड - ***समाज, दलित महिला, स्थिति, जाति, समस्याएं।***

----------X----------

परिचय

दलित महिलाएं, दलित समुदाय की पहचान के साथ-साथ जाति, सभ्यता, और संस्कृति के वाहक के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐतिहासिक रूप से, औपनिवेशिक शासकों और उच्च जाति के कुलीन भारतीयों दोनों ने दलितों को असभ्य, नम्र, बर्बर और निश्चित रूप से सभ्यता और संस्कृति की कमी के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, बड़े भारतीय समाज में पहचाने जाने, स्वीकार करने और आत्मसात करने के लिए, दलितों ने सभ्यता और संस्कृति को महत्वपूर्ण बताया। हालांकि, ऐसा करने में, अंबेडकर और बड़े समुदाय सहित कट्टरपंथी, आधिकारिक दलित पुरुषों ने दलित महिलाओं पर औचित्य और सम्मान के लिंग संबंधी मानदंडों का बोझ डाला।1 उन्होंने महिलाओं के लिए आधुनिकता और शालीनता पर जोर दिया और इस प्रक्रिया में दलित महिलाओं की सामाजिक और यौन खुद को नियंत्रित करने की मांग की। इस प्रकार, अनिश्चितताओं, चिंताओं और अस्पष्टताओं ने विशेष रूप से दलित कट्टरवाद को धमकी दी। जैसे-जैसे जाति लिंग को पीछे छोड़ती जा रही है, समुदाय के खिलाफ हिंसा पर जोर घरेलू हिंसा के आलोचकों को चुप करा देता है। भारत में मूल रूप से महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, और उनके साथ पुरुषों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। महिलाओं ने हमेशा समाज में पुरुषों द्वारा प्राप्त एक अलग स्थान पर कब्जा कर लिया है, महिलाओं को सामाजिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है। प्रत्येक समाज में अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं, उच्च पदों पर महिलाएं और निम्न पदों पर भी महिलाएं होती हैं, लेकिन हर सम्मान पिछड़ों की श्रेणी में आता है। दलित समुदाय भारतीय सामाजिक स्तरीकरण का सबसे निचला स्तर है। दलित सामाजिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित हैं और भारत में दास और दलित महिलाएं कार्यस्थल और घर में इस्तेमाल और शोषित श्रम के साथ वस्तु गरीबी को मिलाकर सबसे खराब तरह का अस्तित्व जीती हैं।2

नारीवादी समाजशास्त्री गेल ओमवेट ने भारतीय दलित महिलाओं को "दलितों में दलित" डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू जाति और वर्ग व्यवस्था को उचित रूप से वर्णित किया। पूछा गया, हिंदू जाति व्यवस्था मिट्टी के बर्तनों का पिरामिड है, जिसमें एक बर्तन सबसे ऊपर और दूसरा सबसे नीचे होता है इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर और शूद्र और अछूत सबसे नीचे होते हैं, लेकिन इसके भीतर प्रत्येक मिट्टी के बर्तन में पुरुष होते हैं। ऊपर और महिलाएं नीचे हैं, और दलित महिलाएं नीचे हैं। संविधान का 73 वां संशोधन महिलाओं सहित अब तक सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों को बहु-संघीय संस्थानों यानी पंचायत राज संस्थानों के सदस्यों के रूप में संवैधानिक प्राधिकरण के साथ जमीनी स्तर की विकास प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक

www.ignited.in

कदम है। ये जमीनी स्तर की संस्थाएं सत्ता के विकेंद्रीकरण के संवैधानिक दायित्व के रूप में अस्तित्व में आई हैं और इसने उन सामूहिकताओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं की मुख्यधारा से बाहर थे। सत्ता संरचना तक उनकी पहुंच की जड़ें बहुत गहरी थीं। सामाजिक मूल्य और मानदंड भेदभावपूर्ण और शोषक थे जिसने उन्हें सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोका है। संक्षेप में, कई सदियों से मौजूद सामाजिक पदानुक्रम ने जातियों को सामाजिक प्रक्रियाओं तक पहुंच से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। कुछ जातियों को सामाजिक प्रक्रियाओं से रोकने की यह धारणा जाति व्यवस्था में अंतर्निहित है। भारतीय समाज को प्रकृति में 'विशिष्ट-अभिलेखात्मक' (पार्सन्स, 1964) के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार की सामाजिक स्थिति में शक्ति, और अधिकतर मामलों में उच्च जातियों में जन्म लेने वालों के लिए धन अर्जित होता है। जाति स्थिति-निर्देशक है और एक व्यक्ति जन्म से ही सामाजिक रैंकिंग प्रणाली में अपनी स्थिति जानता था। साथ ही, एक स्थितिबद्ध समाज में, सत्ता आमतौर पर सामाजिक पदानुक्रम में प्रत्येक जाति को दिए गए रैंक के अनुसार निर्धारित की जाती है। जाति व्यवस्था, पदानुक्रमित और भेदभावपूर्ण, प्रकृति में विशुद्ध रूप से जन्म पर आधारित है, विभिन्न जातियों को सामाजिक संभोग करने से रोकने के लिए स्थायी रूप से निश्चित ब्लॉक में पतित हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, सामाजिक पदानुक्रम के नीचे के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखा गया।3

दलित

जाति का एक लंबा इतिहास रहा है, हिंदू मान्यता के अनुसारय भारत की जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के गठन को क्रमबद्ध कर रही है। परंपरागत रूप से, चार जातीय समूहों और जातियों के दलालों के लिए बहिष्करण की एक श्रृंखला होती है। पिछले 3,000 वर्षों से निम्नतम श्रेणी के दलित भारतीय समुदाय में, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, शैक्षिक घरों और भूमि के स्वामित्व तक पहुंच आमतौर पर उपयुक्त संसाधनों जैसे कि कुओं, गाँव के पानी के पाइप, सड़कों, बसों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में उपयोग की जाती है। दलित वे लोग हैं जिन्हें समाज में नाबालिग और अपमानजनक माना जाता है, और इसलिए अछूत या छुआ हुआ होने के कारण उन्हें "अपवित्र" माना जाता है। "दलितों को इस जाति के पदानुक्रम के निम्नतम स्तर पर रखा गया है।" पवित्रता और प्रदूषण "एक सामाजिक स्थान है और उनके पास है। पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित है कि वर्तमान स्थिति लगातार बदल रही है।4 निकायों की निगरानी के लिए, नेताओं के साथ काम करना, शौच करना बहुत से लोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास करते हैं, दूसरों को उनके स्पर्श से परागित किया जाएगा, या उनकी छाया के माध्यम से इस तरह के प्रदूषण से बचने के लिए, कई समुदायों की सुविधाएं जैसे स्कूल, मंदिर, कुएं, पानी टैंक आदि दलितों में भेद करते हैं। आज के दिनों में, विभिन्न क्षेत्रों में दलित गांवों के लिए हज रखा और खारिज कर दिया गया है। दलित समुदायों के पास बड़े-बड़े कुएं हैं। दलित बच्चे कक्षाओं में अलग बैठते हैं। उन्हें पूरे भारत में कई मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। भेदभाव के ये कार्य ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कम होने के बावजूद होते हैं।5

दलित शब्द मूल शब्द "दल" से बना है जिसे हिब्रू दल से संस्कृत में उधार लिया गया है, दो अर्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह या तो शारीरिक कमजोरी और कमजोर दिमाग या समाज में दो कम महत्वहीन पदों के संयोजन में उपयोग किया जा सकता है। एक और हिब्रू मूल शब्द 'एनी' यह वर्णन करता है और आर्थिक संबंध। दाल एक मौखिक जड़ से ली गई है जो यह मानती है कि गरीबी असमान होने की एक प्रक्रिया है जो बहाया जाता है, सूख जाता है, पतला हो जाता है इसलिए गरीबों की सामाजिक उर्वरता होती है। वे काम की गुणवत्ता रखने वाले लोग हैं और प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ हैं, उनके कमजोर के कारण उन्हें आसानी से कुचल दिया जाता है और उनके प्रभुत्व और दमन के बाद ठीक होने के साधन नहीं होते हैं।6

दलित की परिभाषा

दलित को भारतीय जाति व्यवस्था का अंतिम घटक माना जाता है। दलितों को प्राचीन काल से अपमान, अज्ञानता, निम्न स्तर के काम और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के अधीन किया गया है। इन सबने उनकी एक अलग पहचान बनाई। दलित शब्द अलग-अलग परिभाषाओं में बना है। इन स्थानों पर ये परिभाषाएँ ली गई हैं। अपने समकालीन उपयोग में दलित की सबसे उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा लिखे गए पत्र के रूप में आती है।7

1. प्रो. गंगाधर पंतवने

दलित एक जाति नहीं है, वह अपने देश की सामाजिक और आर्थिक परंपराओं द्वारा शोषित व्यक्ति है। वह ईश्वर पुनर्जन्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, पवित्र पुस्तक अलगाववाद भाग्य और स्वर्ग सिखाती है क्योंकि उन्होंने उसे गुलाम बना दिया है। वह मानवतावाद में विश्वास करता है।8

2. मार्क्सवादी

दलित को वर्ग के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा, जिसमें आम तौर पर महिला जनजाति के श्रमिक और खेतिहर मजदूर शामिल हैं, दलितों को उत्पीड़ित, सांस्कृतिक रूप से अधीन और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। अस्पृश्यता और पवित्रता और प्रदूषण के सिद्धांत, तय करते हैं कि दलित क्या हैं और उन्हें अनुमति नहीं है रहने के लिए, जाने के लिए या बैठने के लिए, जो वे कर सकते हैं और खाने के लिए पानी नहीं दे सकते हैं या दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में विस्तार से शादी कर सकते हैं। दलित समुदाय में, उपजातियों के कई विभाग हैं।9 दलित नेताओं को काम में विभाजित किया गया है। सड़क मजदूर, गोभी, खेत मजदूर और बाद की हैंडबुक को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे कम आम माना जाता है, परंपरागत रूप से, कब्र कब्र खोदना, मरे हुए जानवरों को निकालना और जनशक्ति को साफ करना देश के विशाल बहुमत में 40 मिलियन लोग हैं जो दलित हैं रोजगार के अवसर दलितों को स्कूल में पर्याप्त रोजगार मिलता है गरीबी और भेदभाव के कारण, कई दलित गरीब और अशिक्षित हैं दलित स्वास्थ्य में भी बहुत गरीब हैं।10

भारत में दलित

भारत को मानव इतिहास में जाति के अजीबोगरीब रूप के साथ सभी ज्ञात समाजों में सबसे अधिक स्तरीकृत माना जाता है। जाति व्यवस्था इस मायने में अजीब है कि यह सबसे बड़ी अलग करने वाली ताकतों में से एक है जिसका इस्तेमाल मनुष्य को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित करने के लिए किया गया हैय ऊँची जातियाँ और नीची जातियाँ। यह सरल विभाजन कुछ धार्मिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित है, जो समाजशास्त्री 'पवित्रता' और प्रदूषण की अवधारणाओं के अनुरूप हैं।11 ये धार्मिक प्रतिबंध पूरे इतिहास में चुनौती दिए जाने के बाद भी भारतीय जाति व्यवस्था की वैधता का नवीनीकरण संभव बनाते हैं। इस प्रकार सुपर ऑर्डिनेशन और अधीनता के असंख्य रूपों के साथ जाति व्यवस्था अभी भी भारत के सभी क्षेत्रों में कठोरता के विभिन्न अंश मौजूद हैं। भारत में जाति व्यवस्था न केवल युग-वृद्धावस्था की गहराई-उन्मुख सामाजिक-सांस्कृतिक घटना है, बल्कि यह इन आधुनिक समय में भी काम कर रही है, पूरे भारत में दलितों को अभी भी समाज में अछूत माना जाता है। भारत में दलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं। वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत, आर्थिक रूप से बहुत गरीब और उच्च जाति के राजनीतिक प्रभुत्व वाले हैं, वे आधुनिक युग में अपनी अच्छी स्थिति के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण दलितों की स्थिति शिक्षा और व्यवसाय के मामले में बहुत खराब है।12

दलित महिलाए

दलित महिलाएं सामाजिक शक्ति एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वह असली निर्माता है और औद्योगिक संस्कृति में उनका प्रमुख चेहरा है। वह औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाती है। वह सड़कों पर कपड़ा मिल, सीमेंट कारखानों, अस्पताल और खेतों में काम करती है, दलित महिलाओं का योगदान 80 है। यदि श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। वह परिवार की देखभाल करती है। वह पानी, चारे के ईंधन वगैरह का पता लगाने के लिए मीलों मील चलती है। मुर्गे के बांग देने से पहले वह उठ जाती है। उसके दिन की शुरुआत खेत के सामने गाय के गोबर में मिला हुआ पानी छिड़कने से होती है। जैसे ही सूरज उगता है, वह खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है। वह शाम को वापस आती है और अपना नियमित घरेलू काम शुरू करती है। वह बहुत कम खाती है और वह देर से दाहिनी ओर सोती है और वह पैच वाले कपड़े पहनती है। परिवार, समाज और राष्ट्र के इतने मेहनती समर्थक और निर्माता, आज भारत में बहुत पीड़ित हैं। वह अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, वह दलित होने और एक महिला होने के नुकसान से भरा जीवन जी रही है।13

अनादि काल से लोककथाओं ने हर बच्चे के लिए पहली शिक्षक के रूप में माँ की स्तुति की है। प्रत्येक देश में प्रत्येक मानव बच्चा अपनी माँ के रूप में अपना प्रारंभिक सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। बच्चों के लालन-पालन और उन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत सौंपने में मां का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एक शिक्षिका और संस्कृति की एक कुशल संरक्षक के रूप में महिला की भूमिका के महत्व को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। मानव विकास, उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में महिलाओं का योगदान सर्वविदित है। कोई भी समाज अपने विकास की कल्पना महिलाओं के बिना विविध और बहुमुखी भूमिका अदा किए बिना नहीं कर सकता। मानव अर्थव्यवस्था अपने विकास और विकास के विभिन्न चरणों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संभव हुई है। इसी प्रकार राज्य, उसकी राजनीति और प्रशासन के निर्माण में महिलाओं का योगदान किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं है।14

दलित महिलाएं- मुद्दे और दृष्टिकोण

दलित महिलाओं का विषय समकालीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, विशेष रूप से नए सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में जो आज अपने लोकतांत्रिक स्थान को

कम करके खामोश कर दिए गए हैं। दलित महिला शब्द का प्रयोग करके हम एक कल्पित श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं। यह कहीं भारतीय नारीवादी आंदोलन और दलित आंदोलन के बीच में है। गैब्रिएल डिट्रिच ने अपने अत्यंत संतुलित लेख दलित आंदोलन और महिला आंदोलन में जाति और पितृसत्ता के बीच अंतर्संबंधों पर चर्चा करते हुए बताया, जाति को एक विवाह चक्र और सजातीय विवाह के रूप में देखा जाना चाहिए जो महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण से संबंधित है।15 दलित चेतना का मूल शोषण और दमन के विरोध में बना है। संक्षेप में 'दलित' शब्द का अर्थ परिवर्तन और क्रांति है, 'दलित महिला' शब्द का प्रयोग करके हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि दलित जाति और दलित चेतना से महिलाएं अपने लिए निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए जगह बनाती हैं, यानी। यदि वे प्रजा या एजेंट या स्वयं बन जाते हैं, तो वे सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से नारीवादियों और दलित आंदोलनों को नया नेतृत्व प्रदान करेंगे। वास्तव में, जब हम विकास प्रक्रिया में महिलाओं के हाशिए पर जाने या गरीबी के नारीकरण, या असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के योगदान जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, तो हम इस विशिष्टता के बारे में जागरूक हुए बिना दलित महिलाओं की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता-पूर्व काल में दलित महिलाओं ने अम्बेडकर के नेतृत्व वाले आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आज हम स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए तथाकथित 30ः आरक्षण के खिलाफ गैर-विरोध देखते हैं, जो आगे चलकर दलित महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना से इनकार करता है।

दलितः सामाजिक बहिष्कार और शक्तिहीनता

एक अवधारणा के रूप में सामाजिक बहिष्कार अधिक उपयुक्त और व्यापक शब्द है जो उन अनिश्चित परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिनमें दलित भारत में रह रहे हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार जाति व्यवस्था का प्राकृतिक परिणाम है। दलित, गरीबी से त्रस्त, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, आर्थिक रूप से गरीब, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, राजनीतिक रूप से असंगठित और सांस्कृतिक रूप से बर्बर लोग कहे जाने वाले, भारत में सामाजिक भेदभाव के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। इनमें से अधिकांश भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं।16 उन्होंने असंगठित क्षेत्र में सस्ते मजदूर के रूप में काम किया। वे आर्थिक रूप से अन्य लोगों पर निर्भर हैं, ज्यादातर गांवों में जमींदारों। राजनीतिक रूप से अत्यधिक असंगठित क्योंकि उनकी संख्या अन्य प्रभावशाली जातियों की तुलना में कम है, उनकी अल्पसंख्यक स्थिति 'शक्तिहीनता' का मुख्य कारण है। उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की श्रेणी में आते हैं। उन्हें भारत में वंचित वर्गों और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहिष्कृत समूहों के रूप में जाना जाता है। दलितों ने अतीत में काफी भेदभाव का सामना किया है और अब भी सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में ऐसा करते हैं। जबकि राज्य ने आर्थिक विकास की शुरुआत की है, वास्तव में, सरकारें कई लोगों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में सफल रही हैं। बहुत से दलित अभी भी गरीब हैं, और गरीबी के स्तर से नीचे की आबादी वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं।17

स्वतंत्रता के बाद के भारत ने एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण संविधान में समाहित समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए रणनीतियाँ और योजनाएँ विकसित की हैं। भारत के संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सुनिश्चित किया। जाति, वर्ग, जातीयता और अन्य प्रकार के भेदभाव पर आधारित सभी भेदभावों को कानून के तहत अवैध और दंडनीय माना गया है। कानून के सामने सब बराबर हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दलितों के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और अन्य संवैधानिक निकायों में सीटों के आरक्षण की शुरूआत ने एक समतावादी समाज की शुरुआत की है। संविधान के 73वें संशोधन में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य का दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों को जमीनी स्तर पर विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करे। संशोधन का उद्देश्य भारतीय समाज के उन वर्गों को संवैधानिक अधिकार देना है जो अब तक सत्ता संरचना के दायरे से बाहर थे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों को अब संघीय शासन प्रणाली के सदस्यों के रूप में विकासात्मक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। इसने उन्हें सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है और यह उन्हें सत्ता संरचना का हिस्सा और पार्सल बनने में सक्षम बनाता है, जिसमें उच्च जातियों, जमींदारों, सामंती सरदारों आदि के ग्रामीण अभिजात वर्ग का वर्चस्व था। ग्रामीण सत्ता संरचना में इन परिवर्तनों ने ग्रामीण अभिजात वर्ग को झुका दिया है। और उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर अपनी पकड़ खोने की प्रक्रिया में एक झटके का अनुभव किया है। यह संशोधन समावेशी नीति अपनाकर ओबीसी, दलितों और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। क्या सामाजिक समावेश, सभी को सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसरों के माध्यम से वास्तव में हो रहा है, या यह उन्हें प्रक्रिया में शामिल करने के लिए केवल एक कदम आगे है, बिना उनकी आवाज उठाए आधिकारिक गवाहों को अनुभवजन्य रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है।18 क्या उन लोगों की प्रशंसनीय आवाज, जो सदियों से जाति व्यवस्था में अंतर्निहित रणनीतियों और सामाजिक नीतियों द्वारा

खामोश रहे हैं, यह अब उचित प्रश्न पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुनाई देती है।

दलित पहचान और विचारधारा का विकासः एक ऐतिहासिक अवलोकन

भारतीय पूर्वी इतिहास के विभिन्न चरणों में, दलितों को तत्कालीन हिंदू धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवाद के बारे में अलग तरह से संबोधित किया गया था। हालाँकि, अखिल भारतीय स्तर पर, दलितों ने समान स्तर की छुआछूत या अन्य प्रकार के उत्पीड़न का समान रूप से सामना नहीं किया थाय उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता था और उन्हें अलग-अलग आर्थिक भूमिकाएँ सौंपी जाती थीं। ऐतिहासिक रूप से, अस्पृश्यता के विभिन्न चरणों का पता लगाने के लिए और उनके संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली उस समय की उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करती है। बौगी का हवाला देते हुए, प्रसाद (1970) कहते हैं, "अछूत से मुख्य रूप से घृणा नहीं की जाती हैय वह पुरुषों के किसी भी वर्ग के संपर्क में आने की अपनी शक्ति के लिए डरता है।" आत्म-पहचान की खोज और सामूहिक राजनीतिक हित की अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, पहली बार 'दलित' शब्द का प्रयोग मराठी साहित्य में सांस्कृतिक संदर्भ में बाबासाहेब अम्बेडकर या के अनुयायियों द्वारा किया गया था। नव-बौद्ध लेखकों, महाराष्ट्र के दलित पैंथर्स ने 1972 में अमेरिकन ब्लैक पैंथर्स से प्रेरणा ली।19

डॉ. सिद्धलिंगैया ने अपने नाटक "पंचमा" (द फिफ्थ-वन) में दलित पहचान को दो अलग-अलग स्तरों पर चित्रित किया है, (1) ऊपर की ओर गतिशील दलित जो आधुनिक दलित पहचान के निर्माण के विभिन्न चेहरों को उसके सभी अप्रमाणिक रूपों में प्रस्तुत करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और अधिनियम में पकड़े जाते हैं और अपने अतीत के प्रति जानबूझकर भूलने की बीमारी का रवैया दिखाते हैं। (2) नया दलित, जो न केवल अपने अतीत को भूलने से इंकार करता है, बल्कि उसे जानबूझकर याद भी करता है। उनके अनुसार, पहली श्रेणी को "एक ऐसे क्रांतिकारी माहौल की आवश्यकता है जो उनकी दलित पहचान को स्वीकार और सम्मान करे, जो केवल एक मजबूत आंदोलन प्रदान कर सकता है। एक स्तर पर संपूर्ण दलित आंदोलन इस धारणा से शुरू होता है कि पहले चार को अंततः बदल दिया जाएगा।

अम्बेडकर और दलित विचारधारा

अम्बेडकर दलित अधिकारों के सबसे प्रमुख वक्ता हैं। उन्होंने दलितों की सामाजिक दृष्टि, विचारधारा, पहचान और राजनीतिक कार्रवाई में एक आदर्श बदलाव किया। उन्होंने सामाजिक क्रांति को दलित विकास के समाधान के रूप में प्रचारित किया जाति व्यवस्था का उन्मूलन, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित एक नए समाज का निर्माण, वह बहुआयामी थाय वह एक प्रोफेसर, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक, महान अर्थशास्त्री और दूरदर्शी, भारतीय संविधान के निर्माता और भारत में दलित वर्गों के नेता थे। दलित वर्गों में से कुछ उच्च शिक्षितों में से एक होने के नाते, उन्होंने सामाजिक सुधार और राजनीतिक शिक्षा के लिए उनके बीच आंदोलन का नेतृत्व किया। पहली बार, अम्बेडकर ने दलितों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की योजना बनाई। इन दोनों को मिलाकर, अम्बेडकर ने कल्पना की कि केवल सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित दलित ही जाति व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं। "अम्बेडकर," ने अपनी एकीकरण की नई विचारधारा में, "दलितों के लिए एक स्वायत्त सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया, जो ब्राह्मणवादी हिंदू समाज में उनके पास मौजूद एक से स्पष्ट रूप से अलग था। अम्बेडकर को एक 'गतिशील और करिश्माई' के रूप में भी देखा जाता है। जीवन में नेता, जो मरणोपरांत एक सांस्कृतिक नायक बन गए, 'अछूतों' के लिए एक देवता बन गए, जिन्होंने उन्हें जाति निर्धारण, प्रतिस्पर्धा, टकराव और राजनीति के पुनः उपयोग की प्रक्रियाओं के माध्यम से नेतृत्व किया।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने दलित दृष्टि को बदल दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था और उसके भेदभाव से लड़ने के लिए 'अछूतों' को तैयार किया। उन्होंने दलितों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए एक विचारधारा की कल्पना करते हुए दलितों का नेतृत्व किया। उन्होंने न केवल दलितों के आर्थिक विकास के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदू पहचान के खिलाफ एक वैकल्पिक पहचान की सोच के लिए भी तर्क दिया, जिसने उन्हें नीचा और नीचा रखा। अम्बेडकर की दृष्टि और पहल समकालीन दलित आंदोलन को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। पहली बार दलितों ने अम्बेडकर के नेतृत्व में सर्वोच्च विचारधारा के साथ, व्यवस्थित रूप से जाति व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए 'अछूत', महाराष्ट्र के महारों को संगठित किया। अपने जाति-विरोधी आंदोलन में उन्होंने जो कार्यक्रम अपनाए उनमें शामिल हैंः

(1) 1927 में महाड़ जल टैंक आंदोलन,

(2) 25 दिसंबर, 1927 को मनुस्मृति जलाना,

(3) जाति हिंदू और अछूत एकता के लिए 1928 में समाज समता संघ का गठन,

(4) संघर्ष के लिए 1929 में समता सैनिक दल का गठन जाति उत्पीड़न,

(5) 1930 में नासिक में मंदिर प्रवेश आंदोलन,

(6) 1936 में हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय और,

(7) 1956 में बौद्ध धर्म में सामूहिक रूपांतरण।

अम्बेडकर का मानना था कि जब तक दलित हिंदू धर्म के दायरे में रहेंगे तब तक वे जाति व्यवस्था से नहीं बच सकते और इसलिए, हिंदू धर्म को खत्म करना ही जातिगत भेदभाव को सीमित करने का उपाय है। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, उन्होंने दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने दलितों के विकास के लिए कदम उठाने और दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल (जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक पुरस्कार, 1932) देने के लिए ब्रिटिश सरकार को कई अभ्यावेदन दिए।20 कांग्रेसियों ने यह मानने से इंकार कर दिया कि 'अछूतों' की समस्या एक राजनीतिक मामला हैय उन्होंने हमेशा इसे सामाजिक करार दिया। फिर भी, बदलते भारत में 'अछूत' भी एक राजनीतिक शक्ति ग्रहण कर रहे थे।

निष्कर्ष

समाज में दलित महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याएं, इस मुद्दे पर खुद दलित महिलाओं द्वारा एक नारीवादी स्थिति पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहस पुरुषों की बलात्कार की कल्पनाओं में विचलित करती है। दलित महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करने वाली बुनियादी समस्या और इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को उनकी असहाय निर्भरता से रोजगार के पर्याप्त अवसर, सीमित कौशल, अशिक्षा, सीमित गतिशीलता और स्वायत्त स्थिति की कमी के कारण होती है। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दलित महिलाओं के उत्थान की कई योजनाएँ हैं। लेकिन, ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ बहुत कम ही उन तक पहुंच पाता है।उनकी दुर्दशा अंतहीन है; जीवन कठिन और दुखों से भरा है। अपने लोकतांत्रिक स्थान को संकुचित करने के कारण आज नए सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में दलित महिलाओं का मुद्दा समकालीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण महत्व है।

संदर्भ

1. थोराट,एस. और ली, जे. (2005) जाति भेदभाव और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 30(39) पीपी. 4198-4200।
2. थोराट,एस. (2002) 1990 के दशक में उत्पीड़न और दलित भेदभाव से इनकार। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 9 फरवरी, 37(6) 572-578।
3. एलन टी. एंड ए., थॉमस, (1992), "दलित गरीबी और विकास", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 81।
4. अम्बेडकर, बी. आर., (1946), शूद्र कौन थे? कैसे वे चैथे वर्ण में आए इंडो-आर्यन सोसाइटी, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे 29।
5. बसु,ए (1970), "भारत में शिक्षा और जाति व्यवस्था की वृद्धि, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 181।
6. चतुर्वेदी, जी (1985) भारत में दलित शिक्षा, आरबीएसए प्रकाशन, जयपुर, 124।
7. डेकार्ड, बी.एस.(1979) दलित आंदोलन, हार्पर और रो, न्यूयॉर्क,171
8. एलन टी. एंड ए, थॉमस, (1992), ष्दलित गरीबी और विकासष्, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
9. अम्बेडकर, बी.आर, (1946), शूद्र कौन थे? कैसे वे में चैथा वर्ण बन गए? इंडो-आर्यन सोसाइटी, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे।
10. बसु,ए, (1970), ष्भारत में शिक्षा और जाति व्यवस्था का विकास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
11. चतुर्वेदी, जी, (1985), भारत में दलित शिक्षा, आरबीएसए प्रकाशन, जयपुर।
12. दास, आर.एम, (1993), एजुकेशन इन मनुज फिलॉसफी, एएसबी प्रकाशन, जालंधर।
13. डेकार्ड, बी.एस, (1979), दलित मूवमेंट, हार्पर एंड रो, न्यूयॉर्क।
14. देसाई।एन, (1985), भारतीय दलित, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे।

15. मेनन,एम, इंदु, (1981), भारत में दलित महिलाओं की स्थिति, उप्पल प्रकाशन, नई दिल्ली।

16. पाल, बी.के, (1989), दलितों की समस्याएं और चिंताएं, एबीसी प्रकाशन, नई दिल्ली।

17. राम, आर, (2003), अनुसूचित जातियों की शिक्षा, मयूर प्रकाशन, चेन्नई।

18. राव,एम.एस, (1997), शिक्षा, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

19. रेगे, वाई.एम, (1938), व्हेयर दलित, पॉपुलर बुक, बॉम्बे।

20. व्यास, ए, (1993), भारत में दलित अध्ययन, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।

Corresponding Author

Neha Maurya*

Research scholar, Sociology department, Lucknow university, Lucknow